

नवभारत



भारत-कोरिया साझा व्यापार करेंगे



10 साल में 7 पीएम, बड़ी नाईसाफी है!



यूपीआई पर नई सुविधाएं उपलब्ध



रोनाल्डो ने बनाया रिकॉर्ड

एक नजर में

विनय जॉर्ज उरुग्वे में भारत के नए राजदूत नई दिल्ली. भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विनय जॉर्ज को दक्षिणी अमेरिकी देश उरुग्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. श्री जॉर्ज विदेश सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी हैं और अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. मंत्रालय ने उम्मीद जतायी है कि वह जल्द ही अपना पदभार संभाल लेंगे. भारत और उरुग्वे के बीच राजनयिक संबंध 1960 में स्थापित हुए थे. दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं.

प्रधानमंत्री मोदी को ईरान का न्यूता नई दिल्ली. ईरान में सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं. इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है. यह निमंत्रण अंतरराष्ट्रीय नेताओं को भेजे जा रहे आमंत्रणों की श्रृंखला का हिस्सा है. सूत्रों के अनुसार, खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम 4 जुलाई 2026 से शुरू होकर 9 जुलाई 2026 तक चलेगा. कार्यक्रम का शुरुआत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रेंड मोसल्ला में होगी, जहां 4 और 5 जुलाई को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है.

भारत डायनामिक्स को 1,348 करोड़ का ऑर्डर नई दिल्ली. भारत डायनामिक्स को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 1,347.71 करोड़ रुपये का सैन्य ऑर्डर मिला है, जिसमें हेलीकॉप्टर पर लगने वाले मिसाइल लॉन्चर भी शामिल हैं. इस ऑर्डर में 1,109.37 करोड़ रुपये के हेलिना लॉन्चर और लाइन रिफ्लेसेबल यूनिट्स और 238.34 करोड़ रुपये के काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम एलआरयू शामिल हैं. भारत डायनामिक्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट 24 से 60 महीनों में पूरा किया जाएगा.

गुस्ताखी माफ



रणनीतिक कवायद

टीएमसी व शिवसेना उद्धव गुट के बागियों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में स्थान

मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बागी सांसदों को मिलेगा स्थान

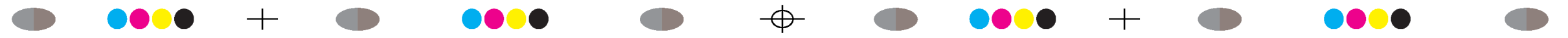
प्रवेश कुमार मिश्र नई दिल्ली, 24 जून. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, यह तो स्पष्ट नहीं हो सका है लेकिन इस विस्तार में देरी क्यों हो रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि यह देरी किसी प्रशासनिक कारण से नहीं, बल्कि संसद के भीतर दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा सुरक्षित करने की एक सोची-समझी रणनीतिक कवायद है. सूत्रों कि माने तो पश्चिम

बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद तुणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों के विद्रोह और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल और विलय पर दिए जाने वाले अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है. ताकि संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कलम के तहत इनकी सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट हो जाए. कहा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा

बागी गुट की मुख्य सूत्रधार और लोकसभा में टीएमसी की चीफ क्लिप रही काकोली घोष दस्तौदार कैबिनेट मंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार हैं. उनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, या सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं. इसके बाद राज्यमंत्री के तौर पर अरुण रॉय तथा सीम्य चटर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल कर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय समीकरणों विशेषकर उत्तर या दक्षिण बंगाल को साधने का प्रयास किया जाएगा. इसी तरह 6 नए सांसदों के आने से लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी. इस आधार पर इस गुट को भी प्रतिनिधित्व में एक अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री की सीट मिल सकती है.

अध्यक्ष की ओर से इन दलबदलियों को कानूनी हरी झंडी मिलेगी, मोदी मंत्रिमंडल का नया गठबंधन-2.0 स्वरूप देश के सामने होगा. सूत्र बता रहे हैं कि यदि सब कुछ राजग रणनीतिकारों

की रणनीति के अनुसार हुआ तो मंत्रिमंडल में टीएमसी के बागी सांसदों व शिंदे गुट के सांसदों में से कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को स्थान दिया जा सकता है. चर्चा है कि राजग के सत्ता फॉर्मूले के अनुसार, टीएमसी के बागी गुट यानी एनसीपीआई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक या दो राज्यमंत्री का पद मिलने की प्रबल संभावना है. सूत्रों कि माने तो जदयू को उसके कोटे के हिसाब से मंत्रिमंडल में स्थान मिल चुका है (शेष पेज 6 पर)



एमपी में मानसून की 33 जिलों से दस्तक

09 दिन की देरी से आया मानसून

04 दिन में पूरे एमपी को करेगा कवर

भोपाल, 24 जून. मध्य प्रदेश में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून की एंट्री 9 दिन की देरी से हुई है, लेकिन अब इसकी रफ्तार तेज हो गई है. आने वाले कुछ दिनों में यह पूरे राज्य को कवर कर सकता है. इस बीच कई जिलों में आंधी, बिजली और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम पूरी तरह बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बुधवार को आधिकारिक रूप से प्रवेश कर लिया है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून बालाघाट, सिवनी और मंडला जिलों के रास्ते प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है. इसके बाद यह धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल जाएगा. अनुमान है



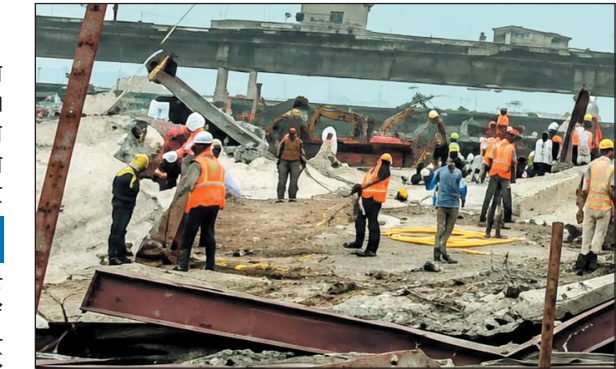
कि अगले तीन से चार दिनों के भीतर मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. राज्य में मानसून इस बार लगभग 9 दिन की देरी से पहुंचा है. सामान्यतः इसकी एंट्री 15 जून के आसपास मानी जाती है. हालांकि, इस देरी के बावजूद प्री-मानसून बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत दी है. भोपाल सहित कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. भोपाल में बुधवार सुबह भी

अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला

ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास

वाशिंगटन, 24 जून. वाशिंगटन में अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मतदान में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई समाप्त करने के पक्ष में 50-48 से प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और परमाणु मुद्दों पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने का संदेश देना है. हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे

अमेरिकी संसद का एक मजबूत राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। मतदान के दौरान चार रिपब्लिकन सीनेटर—रैंड पॉल, सुसान कोलिन्स, लिसा मर्कोव्स्की और 50-48 से प्रस्ताव पारित



कोलकाता, 24 जून. कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब निर्माणाधीन गोदाम की छत

अचानक ढह गई। इस दर्दनाक घटना में जहां तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं बड़ी संख्या में मजदूरों के मलबे के नीचे फंसे

18 अधिकारी-इंजीनियर दोषी करार

लखनऊ, 24 जून. लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड की जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक लापरवाही की एक गंभीर तस्वीर सामने रखी है.

► अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति

► बिलिंग्ग को 'डेथ ट्रैप' बनाने में बड़ी लापरवाही

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जांच में कुल 18 अधिकारी और इंजीनियरों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार पाया गया है. एलडीए ने इन अधिकारियों के

निकास का केवल एक ही रास्ता था

जांच में सामने आया है कि इमारत को 'डेथ ट्रैप' की तरह डिजाइन और उपयोग किया जा रहा था. भवन में प्रवेश और निकास का केवल एक ही रास्ता था, जो आम लगने के बाद धुएं से पूरी तरह भर गया और लोगों के लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया. रिपोर्ट के अनुसार, इमारत का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, लेकिन इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. इसके अलावा, 2016 में जारी ध्वस्तीकरण आदेश को बाद में निरस्त कर दिया गया था, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिला. जांच में यह भी पाया गया कि भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंजाम नहीं थे. न तो कोई इस्मरजेंसी एग्जिट था और न ही धुएं के निकास की उचित व्यवस्था. आग लगने के बाद स्थिति इतनी भयावह हो गई कि दमकल और एनडीआरएफ टीम को दीवार काटकर अंदर प्रवेश करना पड़ा.

खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है. यह दर्दनाक

हादसा सोमवार को एक तीन मंजिला इमारत में हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी.

रणनीतिक कवायद

टीएमसी व शिवसेना उद्धव गुट के बागियों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में स्थान

मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बागी सांसदों को मिलेगा स्थान

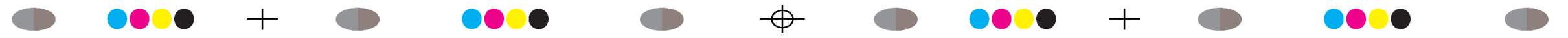
प्रवेश कुमार मिश्र नई दिल्ली, 24 जून. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, यह तो स्पष्ट नहीं हो सका है लेकिन इस विस्तार में देरी क्यों हो रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि यह देरी किसी प्रशासनिक कारण से नहीं, बल्कि संसद के भीतर दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा सुरक्षित करने की एक सोची-समझी रणनीतिक कवायद है. सूत्रों कि माने तो पश्चिम

बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद तुणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों के विद्रोह और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल और विलय पर दिए जाने वाले अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है. ताकि संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कलम के तहत इनकी सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट हो जाए. कहा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा

बागी गुट की मुख्य सूत्रधार और लोकसभा में टीएमसी की चीफ क्लिप रही काकोली घोष दस्तौदार कैबिनेट मंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार हैं. उनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, या सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं. इसके बाद राज्यमंत्री के तौर पर अरुण रॉय तथा सीम्य चटर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल कर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय समीकरणों विशेषकर उत्तर या दक्षिण बंगाल को साधने का प्रयास किया जाएगा. इसी तरह 6 नए सांसदों के आने से लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी. इस आधार पर इस गुट को भी प्रतिनिधित्व में एक अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री की सीट मिल सकती है.

अध्यक्ष की ओर से इन दलबदलियों को कानूनी हरी झंडी मिलेगी, मोदी मंत्रिमंडल का नया गठबंधन-2.0 स्वरूप देश के सामने होगा. सूत्र बता रहे हैं कि यदि सब कुछ राजग रणनीतिकारों

की रणनीति के अनुसार हुआ तो मंत्रिमंडल में टीएमसी के बागी सांसदों व शिंदे गुट के सांसदों में से कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को स्थान दिया जा सकता है. चर्चा है कि राजग के सत्ता फॉर्मूले के अनुसार, टीएमसी के बागी गुट यानी एनसीपीआई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक या दो राज्यमंत्री का पद मिलने की प्रबल संभावना है. सूत्रों कि माने तो जदयू को उसके कोटे के हिसाब से मंत्रिमंडल में स्थान मिल चुका है (शेष पेज 6 पर)



भारत-चीन आत्मनिर्भरता को देंगे बढ़ावा

► पीएम मोदी-वांग यी बैठक में ग्लोबल साउथ पर चर्चा

► दोनों देशों के संबंधों में सहयोग गहरा करने की नई पहल



एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में उदाहरण पेश करना चाहिए. भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. वांग ने कहा कि चीन और भारत, दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं.

10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए विकसित मप्र पर आयोजित कॉन्क्लेव को सीएम ने किया संबोधित

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 24 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया है कि मप्र में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार धरातल पर ला चुकी है. यह दावा उन्होंने बुधवार को राजधानी में विकसित मध्यप्रदेश विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से राज्य में मौजूद

निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि मप्र की विशेषता है कि एक बार जो मध्यप्रदेश आता है, यहीं का होकर रह जाता है. कार्यक्रम में उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि, निवेशक, बैंकिंग और संस्थानों के

प्रतिनिधि तथा नीति निर्माता शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ और एमओयू साइन हुए. मप्र की छवि कृषि प्रधान राज्य के साथ उद्योग मित्र राज्य की भी बनी है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 और अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का संकल्प लिया है. (शेष



मूतक केतन अग्रवाल सिया गोयल चेतन चौधरी

पूछताछ में सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कबूला जुर्म

► शादी से बचने और रिश्ते छुपाने रची थी साजिश

► केतन की मां ने सिया व चेतन के लिए फांसी की सजा मांगी

के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने बताया कि सिया और केतन की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी. इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले कई वर्षों से संपर्क में थे और उनके बीच रिश्ते गहरे थे. घटना लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान हुई, जहां सिया और केतन घूमने गए थे.

वहीं, केतन की मां ने सिया गोयल और चेतन चौधरी के लिए फांसी की सजा की मांग की है. उन्होंने कहा कि सिया ने उनके परिवार को धोखा दिया और जानबूझकर उनके बेटे को रास्ते से हटाया। मां ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने सिया को अपनी बहू की तरह स्वीकार किया था, लेकिन उसी ने उनके परिवार के साथ विश्वासघात किया.

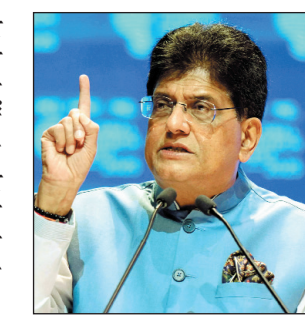
एडवाइजरी में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में बदलते हालात और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है. इसी कारण भारतीय नागरिकों को फिलहाल ईरान की गैर-जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.

गया है कि तेहरान स्थित भारतीय मिशन ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

व्यापार समझौते पर बातचीत तेज

पीयूष गोयल और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच अहम बैठक

नई दिल्ली, 24 जून. भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कई बैठक की हैं. इसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत की गई. यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से बुधवार को दी गई.



केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि एंबेसडर जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के

साथ सुबह कई बैठक हुई हैं. इसमें भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को गहरा करने

के रास्ते तलाशे गए. उन्होंने आगे कहा कि एंबेसडर ग्रीर के नेतृत्व और हमारी बातचीत को रचनात्मक और प्रगतिशील ढंग से आगे बढ़ाने में दोनों टीमों के लगातार प्रयासों की सराहना करता हूँ. इससे पहले मंगलवार को गोयल ने ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की और एक संतुलित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के तरीकों पर चर्चा की. गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत और बढ़ती हुई आर्थिक साझेदारी है.

